back to their native place and rehabtlitation assistance provided to them. The attention of the State Governments has been drawn again to the need to pay particular attention inter-alia, to this problem in a series of Regional Labour Ministers' Conferences held during the latter part of 1994.

कुल जनसंख्या में बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता

3207. **श्री ईश दत्त यादव :**

श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगारों की वर्तमान संख्या कितनी है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इनकी संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने शिक्षित बरोजगार व्यक्तियों की समस्या को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) और (ख) योजना आयोग के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1994-95 के दौरान बेरोजगारों की कुल संख्या 17.9 मिलियन थी । वर्ष 1994-95, 1993-94 तथा 1992-93 के दौरान बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि क्रमश: 0.1, 1.0 तथा 0.0 मिलियन थी। इस अवधि के राज्यवार अनुमान नहीं रखे गये हैं ।

(ग) से (च) बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राज्यों को विशेष अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसा अनुभव किया गया है कि उपलब्ध साधनों का उपयोग उत्पादक रोजगार वृद्धि के सर्जन हेतु किया जाना चाहिए । योजना में परिकल्पित रोजगार नीति से शिक्षितों तथा अशिक्षितों हेतु वास्तविक रोजगार अवसरों के बढ़ने की आशा है ।

इसके अतिरिक्त 2 अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम० आर० वाई०) का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम लगाने पर केन्द्रित है ।

Non Representation of Trade Unions in National Authority on Elimination of Child Labour

3208. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have constituted a National Authority on elimination of Child Labour in hazardous industries, but the trade unions have not been represented thereon;

(b) whether it is a fact that there is a Central Advisory Board on Child Labour and Government have selectively taken only one trade union in it; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir. A National Authority for Elimination of Child Labour has been constituted under the Chairmanship of Union Labour Minister consisting of 10 Secretaries of the Government of India as its members. A copy of the Resolution constituting the Authority is enclosed as Statement-I. (*See* below).